21 वी शताब्दी में भारत–अमरीका सम्बंधो का समीधात्मक अनुशीलन

डॉ. अजय चंद्राकर

विभागाध्यक्ष राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

उतार–चढ़ाव भरे रहे हैं भारत–अमरीका सम्बन्ध

भारत और अमरीका के राजनीतिक सम्बन्ध 65 साल की उम्र हासिल कर चुके हैं। इस दौरान 26 बार भारतीय प्रधानमंत्रियों और एक भारतीय राष्ट्रपति ने अमरीका का दौरा किया जबकि 6 बार अमरीकी राष्ट्रपति भारत आयें। भारत की आजादी के बाद अमरीका से उसके सम्बन्ध शीतयुद्ध के दौर, अविश्वास और भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर खिचाव में बन्धे रहे है। पिछले कुछ वर्षो से इनमें गर्माहट देखी जा रही है। 1949 में अमरीका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, अमरीकी राष्ट्रपति हैरी टूमैन के मेहमान बने। इसके बाद 1956, 1960, 1961 में अमरीका की यात्राएं की। 1959 में अमरीकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर भारत का दौरा करने वाले अमरीकी राष्ट्रपति बने । शीतयुद्ध के दौरान भारत ने तटस्था की घोषणा की थी। पूरे शीतयुद्ध काल में अमरीका से रिश्तों में हिचकिचाहट थी तो रूस और भारत के बीच निकटता बढ़ी । 1974 में परमाणु परीक्षण के साथ भारत सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों के बाद ऐसा पहला देश बना।

भारत और अमरीका में सहयोग – नेहरू युग में अनेक क्षेत्रों में असहमति होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त सहयोग था। पं. नेहरू के शब्दों में, "दोनो देश लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक जीवन पद्धति के प्रति समान विश्वास रखते हैं और शान्ति एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच मैत्री और पारस्परिक सहयोग होना अत्यंत स्वाभाविक है।"

निष्कर्षतः नेहरू युग में अमरीका ने भारत के साथ दोहरी नीति अपनाई– एक तरफ तो भारत के साथ दबाव की नीति अपनाई तो दूसरी ओर भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग भी

किया। अमरीका की इस दोहरी नीति के पीछे अमरीकन राजनीतिज्ञों का मूल उद्देश्य भारत को किसी ढंग से अपने खेमे मे लाना था।

इन्दिरा गांधी युग में अमरीका के साथ भारत का सम्बन्ध नफरत भरी मुहब्बत की विशेष भावना से प्रभावित रहे हैं। राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत–अमरीकी सम्बन्धों में सुधार की दृष्टि से श्रीमती इन्दिरा गांधी से अमरीका यात्रा का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर 18 मार्च, 1967 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरीका की यात्रा की। भारतीय प्रधानमंत्री की की इस यात्रा से यह आशा की जाती थी कि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा किन्तु अमरीका दबाव नीति के कारण कोई अनूकुल परिणाम नही निकला।

अमरीकन दबाव के कारण भारत को रूपये का अवमूल्यन करना पड़ा। भारत–पाक युद्ध के बाद अमरीका ने बंद की गई आर्थिक सहायता को पुनः आरम्भ किया, किन्तु भारत को अमरीका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता नगण्य थी। सन् 1968 में अमरीका ने भारत को जो आर्थिक सहायता स्वीकृत की वह पिछले 20 वर्षो की तुलना में सबसे कम थी, जिसके कारण भारत के योजनाओं पर प्रतिकुल असर पड़ा। अप्रैल 1967 में नागा विद्रोही फीजो का अमरीका में आश्रय दिया गया और 1967 में यह रहस्य पता चला कि भारत अनेक संगठनो के माध्यम से सी.आई.ए. भारत विरोधी में संलग्न है। पश्चिमी एशिया संघर्ष (1967) तथा वियतनाम युद्ध के मुद्दों पर भारत अमरीकी दृष्टिकोनों में व्यापक अन्तर उभर कर सामने आया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अरब राष्ट्रों के पक्ष का समर्थन किया। 1969–70 में वियतनाम युद्ध को लेकर भारत और अमरीका में गहरे मतभेद रहे। 1970 में काम्बोडिया में अमरीकी फौजों के घुसने का भारत ने विरोध किया । भारत स्थित अमरीकन सूचना केन्द्र ने एक प्रकाशन **'सयुंक्त राष्ट्र के बीस वर्ष'** में भारत का क्षेत्रफल 30,46,232 वर्ग किलोमीटर दिखाया, इसमें जम्मू एवं कश्मीर का भाग सम्मिलित नही किया गया था। U-N-Statistical Year Book 1965 में भी ऐसा ही प्रकाशित किया गया जबकि 1 जनवरी 1966 को भारत का क्षेत्रफल 30,68,090 किलोमीटर था। 5 अगस्त, 1970 को इस विषय पर भारत सरकार का ध्यान संसद में आकर्षित किया गया और इस प्रकाशन पर आपत्ति प्रकट की गई। प्रत्युत्तर में विदेश उपमंत्री दिनेश सिंह ने

कहा कि अमरीकन सरकार का इस सम्बन्ध में विरोध पत्र भेजा जा चुका है। अमरीका का यह कार्य भारतीय मैत्री के विरोध मे ही था ।

जब भारत ने 11 एवं 13 मई, 1998 को सफल परमाणु परीक्षण कर आणविक शक्ति बनने के अपने अडिग निश्चय को प्रकट कर दिया तो अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये। क्लिंटन ने परीक्षणों को श्खतरनाक गलती' बताते हुए भर्त्सना की। उन्होने 1994 के अमरीकी परमाणु अप्रसार कानून के तहत प्रतिबन्धो की घोषणा की जिससे सभी द्विपक्षीय सैन्य व आर्थिक मदद तथा भारतीय कम्पनियों को अमरीकी बैंको से ऋण बन्द हो गए। क्लिंटन ने भारत से यह घोषणा भी करने के लिए कहा कि वह और परमाणु परीक्षण नही करेगा तथा बिना कोई शर्त लगाए सी. टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर कर दे। अमेरिका ने पी–5 तथा जी–8 की बैठको में भारत के नाभिकीय परीक्षणों की आलोचना करने के लिए पहल की, बाद में अमरीका भारत की सुरक्षा चिन्ताओं को समझने लगा और भारत के विरूद्ध लगाए गए प्रतिबन्धों को आंशिक रूप से उठाने की घोषणा की। जिनका भारत ने सही दिशा में कदम बताकर स्वागत किया।

1998–2008 नए युग की शुरूआत

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के में अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया। क्लिंटन की भारत यात्रा 21वी शताब्दी में भारत–अमरीका सम्बन्धों की शुरूआत थी। 22 वर्षो के बाद किसी अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत की 5 दिवासीय यात्रा की। इस यात्रा को भारत–अमरीका सम्बन्धों का एक नया मोड़ माना जाता है।

अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा की औपचारिक शुरूआत के पहले दिन क्लिंटन तथा प्रधानमंत्री वाजपेयी ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाए जाने सम्बन्धी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। इस दस्तावेज को दृष्टिकोण पत्र 2000 नाम दिया गया। भारत–अमरीका सम्बन्धो को प्रगाढ़ बनाने हेतु आठ सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई।

क्लिंटन की भारत यात्रा नए दिशा संकेत

• भारत और अमरीका का "दृष्टिकोण – 2000" नामक घोषणापत्र अमरीका के नए इरादों को पकट करता है।

• क्लिंटन ने स्पष्ट कर दिया कि अमरीका भारत के साथ आगे निरन्तर संवाद रखना चाहता है। साथ ही अमरीका भारत की सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताओं को भी समझ रहा हैं।

• क्लिंटन ने हिंसा का विरोध करते हुए पाकिस्तान को भी यह सन्देश दिया कि वह कश्मीर में नियन्त्रण रेखा का सम्मान करे ।

• भारतीय बाजार का खुला होना अमरीका अपने आर्थिक हित में मानता है । साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, साफ्टवेयर और ज्ञान आधारित क्षेत्रों में पहल को भी अमेरीका व्यवसाय की दृष्टि से अपना पूरक मानने लगा है।

• अमरीका दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिरता व शान्ति बनाए रखना चाहता है। साथ ही किसी भी सम्भावित परमाणु टकराव को भी रोकना चाहता है ।

क्लिंटन की इस यात्रा में जहां अनेक महत्वपूर्ण बातों पर सहमति हुई, वहाँ कई मुद्दों पर असहमति बनी रही। जैसे भारत सीटीबीटी पर उसके वर्तमान रूप में हस्ताक्षर करने को सहमत नही हुआ । उसने अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को स्थगित करना भी नही माना। परमाणु अप्रसार सन्धि और परमाणु सामग्री के नियति पर रोक सम्बन्धी विषयों पर भी सीधे समझौते नही हो सके। लेकिन दोनो देशों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को ऐसे टकराव का मुद्दा नही बनाया कि जैसे मैत्री और समझ–बूझ के नए युग का शुभारम्भ करने में बाधक माना जाए।

कुल मिलाकर अमरीका के राष्ट्रपति की यह यात्रा विश्व में भारत के समुचित महत्व का स्थागित करती है।

डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल मे भी भारत–अमरीका सम्बन्धों को मजबूत बनाने हेतु उचित प्रयास किये। राष्ट्रपति बुश भारत–अमरीका सम्बन्धों को नये आयाम देने हेतु 2006 में भारत की तीन दिवासीय यात्रा की। इस दौरान ने भारत को परमाणु सहयोग समझौता किया।

इस समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के कुल 22 परमाणु रिएक्टरो मे से 14 को 14 को अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए खोलने पर राजी हो गये।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इस सहमति के अतिरिक्त कृषि, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ आदि के सम्बन्ध में कई अन्य समझौतो पर हस्ताक्षर भी दोनों पक्षों में हुए है। भारत और अमरीका के बीच परमाणु समझौते से दोनो देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों मे नया मोड़, कई मसलो पर नई पहल के दरवाजे खुले है। राष्ट्रपति बुश के शब्दों में, **"हमारे सम्बन्ध नाटकीय ढंग से बदल गये है..... हमारे बीच अब रणनीतिक साझीदारी है....."**

भारत–अमरीका असैनिक नाभिकीय करार पर 10 अक्टूबर, 2008 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया जाना प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जुलाई 2005 अमरीका की यात्रा के दौरान घोषित असैनिक नाभिकीय ऊर्जा पहल की निष्पत्ति थी। भारत ने अन्तराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ 1 अगस्त, 2008 को भारत विशेष सुरक्षोपाय करार सफलता पूर्वक सम्पन्न किया जिससे अमरीका के लिए एन. एस. जी. दिशा निर्देर्शो के समंजन के लिए 45 सदस्यीय नाभिकीय अपूर्ति कर्ता समूह से सम्पर्क साधने का मार्ग खुल गया। फलतः अमरीकी प्रतिनीधि सभा ने 28 सितम्बर, 2008 को तथा सीनेट ने 1 अक्टूबर, 2008 को करार से सम्बन्धित बिल को मंजूरी दे दी, 18 अक्टूबर, 2008 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमरीकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित भारत–अमरीका असैनिक नाभिकीय करार पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया गया ।

नवम्बर 2009 मे डॉ. मनमोहन सिंह ने अमरीका की चार दिवसीय यात्रा की। स्वागत समारोह में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि वह ऐसा भविष्य बनाना चाहते है जिसमे भारत अपरिहार्य हो। उन्होनें भारत को परमाणु शक्ति के रूप मे स्वीकार किया तथा भारत के साथ अमरीका के असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के कार्यन्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत–अमरीकी साझेदारी की चरण शुरूआत की और इसे **'वैश्विक रणनीतिक की एक नये साझेदारी'** बताया।

लंदन में **2 अप्रैल, 2009** को भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भेंट **जी–20** देशों की बैठक में हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ओबामा से कहा कि भारत और अमरीका के समान सपने और समान दृष्टिकोण है और दोनो ही देश इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर काम करना पंसन्द करेंगें। ओबामा ने भारत की महत्व की तारीफ की क्योंकि अब यह दुनिया में आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है । उन्होनें यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सूझबुझ का विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत को एक वैश्विक साझेदार के रूप में देखता है और दोनो देश मिलकर 21वी सदी की चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और आंतकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते है। उन्होंने ओबामा से कहा कि आपके नेतृत्व में हम लोगो को जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पडेगा। इसके जवाब में ओबामा ने कहा कि अमरीका भारत को अपने वैश्विक सहयोगी के तौर पर देखता है।

भारत–अमरीकी सम्बन्धो की नई शुरूआत

सितम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत–अमरीका सम्बन्ध को प्रगाढ़ बनाने हेतु अपने पहले कार्यकाल के आरम्भ में ही अमरीका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किये, इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने तथा तकनीकी क्षेत्र में निवेश जैसे मुद्दों पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। भारत ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अमरीका के राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान के बीच ज्ञान कार्यक्रमों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग तथा थर्टी मीटर टेलीस्कोप परियोजना में सहयोग पर भी सहमति बनी। साथ ही साथ विजन स्टेटमेण्ट पर दोनो देशों ने सहमति प्रदान की इसके अर्न्तगत– असैनिक परमाणु सहयोग, रक्षा सहयोग, आतंकवाद से लड़ने व आंतरिक्ष सहयोग, व्यापार आर्थिक, ऊर्जा व जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और पौद्योगिकी, स्वास्थ्य क्षेत्र, लोग सम्बन्ध, सांस्कृतिक सहयोग मीडिया आदि कई मुद्दों पर समझौते हुए।

ओबामा की भारत यात्रा से भारत–अमरीका सम्बन्धों को मिला नया आयाम

जनवरी, 2015 मे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का तीन दिवासीय भारत दौरा कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुआ। इससे दोनो देशों के आपसी रिश्तों को नया आयाम तो मिला ही हैं, यह भी साफ हो गया कि सबसे पुराना लोकतंत्र अमरीका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया की सूरत को बदलने की क्षमता रखते हैं। अपनी यात्रा के अंतिम दिन ओबामा ने इस बात का बखूबी जिक्र भी किया कि भारत और अमरीका में काफी समानताएं है, दोनों की चुनौतियां भी एक जैसी है, तो क्यों न हम साथ–साथ चलें । समय की मांग भी यही है। देखा जाए तो भारत आज जहां खड़ा है, इससे आगे बढ़ने के लिए अमरीका जैसे शक्तिशाली देश के सहयोग की काफी जरूरत है। वहीं अमरीका को भी भारत जैसे देश की जरूरत है, यह इसलिए नही कि अमरीका निर्यातक और भारत बड़ा बाजार है, बल्कि यह इसलिए जरूरी है कि दोनों ऐसे देश हैं। जहां सफल लोकतंत्र हैं, धार्मिक व भाषाई विविधता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, समाज न्याय और समानता पर आधारित है। दोनों देशों में सशक्त संविधान कि है जिससे शासन व्यवस्था संचालित होती है। इससे भी अच्छी बात यह हर कोई अपनी मेहनत और लगन से निचले स्तर से शिखर पर पहुंच सकता है। भारत में इसके उदाहरण आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं, तो अमरीका में राष्ट्रपति बराक ओबामा । दोनो समान्य परिवार से आते है।

पहली बार ओबामा ने अपने संबोधन के जरिए भारत से जुडने और दिल के छूने की कोशिश की है। उन्होंने यहां के मूल्यों, भाषाई – जातिगत– धार्मिक क्षेत्रीय विविधता, गरीबी, संघर्ष का इस तरह जिक्र किया जैसे लगा कि उन्होंने भारत का आत्मसात कर लिया है। यह दोनों देशों के बदलते रिश्तों की दस्तान ही है।

भारत को क्या मिला, क्या मिलेगा

विश्व के सबसे बड़े गणतंत्री देश अमरीका के राष्ट्रपति ने जहां विश्व के सब पुराने गणतंत्री देश की यात्रा कर हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बन एक इतिहास बनाया, वही अब राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक चिंतन की इस विश्लेषण में जुट गए कि ओबामा जी की इस भारत यात्रा से भारत को क्या मिला और आगे क्या मिलने वाला है।

दोनों नेताओं की 25 जनवरी की दिनभर की मशक्कत को यदि करीब से देखा जाए तो यह अहसास अवश्य होता है कि भारत के पलड़े में कुछ तो आया है।

जैसे–एयराट तकनीक जिसमें जेट इंजन के विकास, मानव हथियार रहित हवाई जहाज, एयराट लेंडिंग प्रणाली का विकास शामिल है। इसी तरह पिछले दस सालों से न्यूक्लियर लॉयबिलिटी आण्विक जिम्मेदारी की तस्वीर पर जो धुल जर्मी थी उसे भी दोनों नेताओं रे साफ करने का प्रयास किया, इस जिम्मेदारी कपर 6 सालों से अटकी 123 एटमी डील की बाधाएं दूर करने के लिए, भारत ने स्वयं को झुकाते हुए साढ़े सात सौ करोड़ रूपये की सरकारी गारंटी जोड दी है, अब चार भारतीय कम्पनियां साढ़े सात सौ करोड़ का बीमा देगी, बाकी साढ़े सात सौ करोड़ का भार भारत सरकार वहन करेगी। इस आण्विक डील को ओबामा की यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

इसी के साथ अमरीका की आर्थिक मदद से विशाखापट्नम, इलाहाबाद और अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाना व इनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराना, साथ ही भारत अमरीका के बीच दस साल के लिए रक्षा सौदा, जिसमे दोनों देशों की इस क्षेत्र में परियोजनाओं के संयुक्त विकास और उत्पादन पर सहमति भी महत्वपूर्ण है। इससे भारत में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार होने के साथ भारत के घरेलू रक्षा उद्योगों की उन्नति में मदद मिलेगी। इन उपलब्धियों के साथ ही भारत को रक्षा क्षेत्र में और भी कुछ समझौतों की सौगात मिली है। जैसे– खुफिया सूचनाओं और समुद्री सुरक्षा पर दोनों देशों का एकसाथ आपसी सहयोग, जिसके तहत दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया सुचनाओं के अदान प्रदान व समुद्री रक्षा के जरिए रक्षा क्षेत्र में अद्वितीय भागीदारी बढ़ाएंगे । इसके अलावा भारत अमरीका के बीच मौजूदा व्यापार प्रतिशत में 60 प्रतिशत की अभिवृद्धि और इसे एक सौ अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य भी आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला है।

अब निवेश संधि पर दोनों देशों के बीच फिर से विचार विमर्श करने पर सहमति बनी है, उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2000 से नवम्बर, 2014 के बीच अमरीका से भारत में 13.8 अरब डॉलर का निवेश आया था। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी, अर्न्तराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रति चिन्ता और इसे खत्म करने की दिशा में संयुक्त कदम व वैश्विक रणनीति को अपनाने

पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में भारत की पूर्ण सदस्यता और समर्थन पर भी सहमति बनी है। इन सब के साथ एक उपलब्धि यह भी रही कि भारतीय कामगारों के हित में दोनों देशों के बीच करार हुए जिसमें अमरीका में कार्यरत भारतीय कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के खातों में अंशदान जैसे मुद्दे पर विस्तृत समझौते की रूपरेखा तैयार की गई ।

ओबामा ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए पुरजोर समर्थन किया है। ओबामा–मोदी के बीच गहरी दोस्ती भी दुनिया के सामने आयी हैं। कुल मिलाकर बराक ओबामा की यह यात्रा भारत–अमरीका रिश्तों की ऐसी बुनियाद तैयार कर दी है जिस पर आने वाले दिनों में दोस्ती की नई इबारत लिखी जा सकेगी। अमरीकी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा फिलहाल तो भारत के लिए शुभ ही मानी जा रही है, फिर आगे आगे देखिए होता है क्या।